



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रीतिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 1991/आषाढ़ 14, 1913

No. 394]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 1991/ASADHA 14, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ तंत्र की जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रधिकृता

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1991

का.आ. 452 (अ).—प्रादृपति, मंत्रिमंडल के प्रमुखधर्म 22 के बांध (3) द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आंदोलन) नियम, 1961 का और भंगोत्तन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्जाः—

1. (1) इन नियमों का संशिक्षण नाम भारत सरकार (कार्य आंदोलन) द्वारा भी सत्रहवां संशोधन नियम, 1991 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2 भारत सरकार (कार्य आंदोलन) नियम, 1961 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) प्रधम भनुसूची के स्थान पर मिम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्जाः—

“प्रधम भनुसूची

(नियम 2)

मंत्रालय, विभाग, सचिवालय तथा कार्यालय

1. कुचि मंत्रालय

- (1) कुचि मीर सहकारिता विभाग
- (2) कुचि भनुसंधान और शिक्षा विभाग
- (3) पशुपालन और फेरी विभाग

2. रसायन और उर्वरक मंत्रालय

- (1) रसायन और वेटो-रसायन विभाग
- (2) उर्वरक विभाग

3. नागर विभाग और पर्यटन मंत्रालय

- (1) नागर विभाग विभाग
- (2) पर्यटन विभाग

4. नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

5. कोबला मंत्रालय

6. भाषणिय मंत्रालय
 (1) दायित्य विभाग
 (2) पूर्ति विभाग

7. मंत्रालय
 (1) डाक विभाग
 (2) वूरस्वार विभाग

8. रक्षा मंत्रालय
 (1) रक्षा विभाग
 (2) रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग
 (3) रक्षा प्रनुसंधान और विकास विभाग

9. पर्यावरण और वन मंत्रालय

10. विदेश मंत्रालय

11. वित्त मंत्रालय
 (1) आर्थिक कार्य विभाग
 (2) व्यय विभाग
 (3) राजस्व विभाग

12. स्वास्थ्य मंत्रालय

13. स्वास्थ्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

14. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
 (1) स्वास्थ्य विभाग
 (2) परिवार कल्याण विभाग

15. गृह मंत्रालय
 (1) आंतरिक सुरक्षा विभाग
 (2) राज्य विभाग
 (3) राजभाषा विभाग
 (4) गृह विभाग

16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय
 (1) शिक्षा विभाग
 (2) युवक कार्यक्रम और खेल विभाग
 (3) कला विभाग
 (4) मस्कुर्ति विभाग
 (5) महिला और बाल विकास विभाग

17. उद्योग मंत्रालय
 (1) आद्योगिक विकास विभाग
 (2) मारी उद्योग विभाग
 (3) लोक उद्यम विभाग
 (4) लघु उद्योग और हृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग

18. सूचना और प्रसारण मंत्रालय

19. अम मंत्रालय

20. विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
 (1) विधि कार्य विभाग
 (2) विधायी विभाग
 (3) न्याय विभाग
 (4) कंपनी कार्य विभाग

21. जल मंत्रालय

22. संसदीय कार्य मंत्रालय

23. कार्मिक सोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय
 (1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
 (2) भैशाधिक मुद्रा और सोक शिकायत विभाग
 (3) पेशन और पेशन सोमी कल्याण विभाग

24. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

25. योजना और कार्यक्रम कार्यालयन मंत्रालय
 (1) योजना विभाग
 (2) सांख्यिकी विभाग
 (3) कार्यक्रम कार्यालयन विभाग

26. विद्युत और अपारंपरिक ऊर्जा स्वीत मंत्रालय
 (1) विद्युत विभाग
 (2) अपारंपरिक ऊर्जा स्वीत विभाग

27. रेल मंत्रालय

28. आर्मीण विकास मंत्रालय

29. विकास और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
 (1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
 (2) विज्ञान और प्रौद्योगिक प्रनुसंधान विभाग
 (3) आयोटेक्नोलॉजी विभाग

30. इस्पात मंत्रालय

31. जलभूतल परिवहन मंत्रालय

32. वस्त्र मंत्रालय

33. शहरी विकास मंत्रालय

34. जल संसाधन मंत्रालय

35. कल्याण मंत्रालय

36. परमाणु ऊर्जा विभाग

37. इलैक्ट्रॉनिकी विभाग

38. महासागर विकास विभाग

39. अंतरिक्ष विभाग

40. मंत्रिभूतल सचिवालय

41. राष्ट्रपति मंत्रिवालय

42. प्रधानमंत्री कार्यालय

43. योजना प्रायोग
 3. उक्त नियम की हिसीय अनुसूची में :-
 (क) “कृषि मंत्रालय” शीर्षक के प्रधीन “ग. मार्गीण विकास विभाग और घ. उर्वरक विभाग” उप शोषकों और उनके नीचे शी प्रविष्टियों का लोग किया जाएगा।
 (ख) “कृषि मंत्रालय” शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्ननिवित प्रविष्टियां अतःस्पष्टित ही जाएंगी।—
 क. रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग
 1. औषधियां तथा फार्मास्यूटिकल्स।
 2. कीटनाशी (कीटनाशी प्रधिनियम, 1968) (1968 का 46) के प्रशासन के अतिरिक्त।
 3. शोरा-वितरण और मूल्य निर्धारण।

4. ऐलोहूल-ओडीयिक और पेय (ऐसे ऐलोहूलो पेय को छोड़कर जिनका आधार नहीं पर न हो) (भारतीय पावर एन्कोर्स अधिनियम, 1948 (1948 का 22) संहिता ।

5. रंजक-द्रव्य और रंजक मध्यक ।

6. सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विनियोजना आवंटित नहीं किए गए हैं ।

7. विभाग द्वारा अवशुल्क सब उद्योगों की योजना, विकास तथा नियंत्रण सहायता ।

8. इस विभाग के अंतर्गत विनियोजित विषय में से किसी से भी संबंधित सभी संगठन अव्याप्ति कार्यालय अव्याप्ति संगठन ।

9. इस विभाग में सम्मिलित विषयों से संबंधित सरकारी भेद की परियोजनाएं, उन परियोजनाओं को छोड़कर जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विनियोजित आवंटित की गई हैं ।

10. भोपाल में विमोचिका-नस्तंशंखी विशेष विधियाँ ।

11. पेट्रो-रसायन ।

12. सेल्यूलोज रहित नियोजित काइबर (नायलॉन, पोलिएस्टर, एक्सिलिक आदि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग ।

13. मैशिनेट रखड़ ।

14. प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिकों की विक्रेता और प्लास्टिक की डिज़ाइनर वस्तुएं शामिल हैं ।

15. उपर्युक्त मामलों से संबंधित सभी सरकारी भेद के एक ।

16. इस सूची में विनियोजित विषयों से संबंधित सभी संगठन या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।

क्ष. उत्तरक विभाग

- उत्तरक उत्पादन के लिए परियोजना नियार करता जिसके अंतर्गत किसी अधिकृत सरणीकरण अधिकरण के माध्यम से उत्तरकों का आयात भी है ।
- कृषि और सहकारी विभाग द्वारा किए गए ग्राम्यकारों के अनुसार उत्तरकों के संचालन और वितरण की व्यवस्था ।
- वेशी और अव्याप्ति उत्तरकों के लिए उत्पादन का प्रबंध है जिसके अंतर्गत अव्याप्ति उत्तरकों के "प्रतिवर्यारण" मूल्य और लागत का अवधारण भी है ।
- सुर्वरक (संचालन नियंत्रण) आदेश, 1960 का प्रशासन ।
- विभाग के नियंत्रण के अधीन लोक उपकारों के लिए प्रशासनिक उत्तरदायित्व ।
- इस विभाग के अधीन सम्मिलित विषयों से संबंधित परियोजनाएं, तिथाय ऐसो परियोजनाओं के जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विनियोजित रूप से आवंटित की गई हैं ।
- सहकारिता क्षेत्र में, अर्थात् इंस्थित फार्मर्स कोऑपरेटिव, लिमिटेड (आई.एफ.एफ.सी.ओ.) कृषक सारकों कोऑपरेटिव, लिमिटेड (के.प्लार.आई.वी.एफ.सी.ओ.) उत्तरक उत्पादन एकार्कों के लिए प्रशासनिक उत्तरदायित्व ।
- हॉर्डियन पोटाश लिमिटेड (आई.पी.एल.) के लिए प्रशासनिक उत्तरदायित्व ।
- इस विभाग के अधीन विनियोजित विषयों में से किसी से भी संबंधित सभी संगठन या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।

(ग) (i) "नागर विमान मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर "नागर विमान और पर्यटन मंत्रालय" शीर्षक रखा जाएगा ।

(ii) इस प्रकार रखे गए शीर्षक के पश्चात् और उसके नीचे भी प्रविधियों से पहले, निम्नलिखित उप शीर्षक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) "नागर विमान विभाग"

(iii) इस प्रकार अंतःस्थापित "नागर विमान विभाग" उप शीर्षक और उसके नीचे को प्रविधियों के पश्चात् निम्नलिखित उप शीर्षक और प्रविधियों अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(ख) पर्यटन विभाग

- पर्यटन विभाग
- भारतीय पर्यटन विकास नियम और उसके प्रनालीत सरकारी क्षेत्र के होटल । इस सूची में विनियोजित मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े ।
- "नागर विमान और पर्यटन मंत्रालय" शीर्षक और उसके नीचे जारी वाली प्रविधियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय"

- प्रांतिक व्यापार ।
- आन्तरिक व्यापार : स्पिरिट्युक्त निमिति (अन्तरराज्यिक व्यापा और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 (1955 का 39) ।
- वायदा बाजार का नियंत्रण अधीस संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 (1952 का 72) ।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ऐसी आवश्यक वस्तुओं को प्रदाय कीमते और वितरण, जो विनियोजित किसी अन्य मंत्रालय द्वारा व्यवहार नहीं है ।
- जोर बाजारी नियारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7) नियोजित के अध्यधीन व्यक्ति ।
- उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं ।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली ।
- कीमतों का परिवर्तन और आवश्यक वस्तुओं को उपलब्धता ।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) ।
- पैक की हृदृष्ट वस्तुओं का विनियमन ।
- कागूनी भाष्य-विचार में प्रसिद्धण ।
- वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोक जित में समीक्षित है, जहां तक वे वनस्पति धी, तिलहन, बनस्पति तेलों, खली और वसा से संबंध हैं ।
- बनस्पति धी, तिलहन, बनस्पति तेलों, खली और वसा का अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य, उनका मूल्य नियंत्रण पूर्ति और वितरण ।
- बनस्पति धी, बनस्पति तेल और वसा निवेशालय ।
- संप्रतोक और नाम (अनुचित प्रवेश का निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) ।
- बाट और माप मानक । बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) ।
- भारत मामक व्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) ।
- इस सूची में विनियोजित किसी भी विषय से संबंधित सभी संगठन या अधीनस्थ कार्यालय या मूल्य संगठन जिसमें फार्मर्ड भार्केट्स कीमान, बम्बई भी सम्मिलित है ।

(क) इस प्रकार अंतःस्थापित “नामांकित पूर्ति संस्कारित वितरण बंडलेट” शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी।

“कोयला संस्कारण”

- भारत में कोयिंग और नाम-कोयिंग कोयले तथा लिम्नाइट का अवैधत और विकास।
- कोयले के उत्पादन और पूर्ति, वितरण और कीमत से संबंधित सभी मामले।
- इस्पात विभाग जिसके लिए जिम्मेदार है स्वास्थ्य कोयला भारतीयों का विकास और संवालन।
- कोयले का निम्न ताप पर कार्बनीकरण और कोयले से संशोधित तेल का उत्पादन।
- कोयला बाल (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन।
- कोयला बाल भविष्य निष्ठि संगठन।
- कोयला बाल कल्याण संगठन।
- कोयला बाल भविष्य निष्ठि द्वारा प्रकीर्ण उत्पाद अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन।
- कोयला बाल श्रम कल्याण निष्ठि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) का प्रशासन।
- बालों में उत्पादित और प्रेषित कोक और कोयले पर उत्पाद उत्पादन भी और संग्रहण के लिए तथा बचाव निष्ठि के प्रशासन के लिए बाल अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के प्रतीकृत नियम।
- कोयला-धारक धेत्र (उत्पादन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन।
- कोयले और लिम्नाइट से संबंधित सरकारी खेत्र के उत्पाद।
- बाल और बचनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा यथा केन्द्रीय कानूनों का प्रवालय जहां वह कि उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयले और लिम्नाइट और भरणार्थ बाल से है, इस प्रकार के प्रशासन हे प्रसंगवत कार्य जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रबन्ध कामिल हैं।
- (क) “ऊर्जा संसालय” शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(क) “पर्यावरण तथा बन संस्कारण” शीर्षक के अंतीम “पर्यावरण, बन और वन्य जीव विभाग” उप शीर्षक का लोप किया जाएगा।

(ज) (i) “बाल और नामांकित पूर्ति संस्कारण” शीर्षक के स्वाम पर पर “बाल संस्कारण” शीर्षक रखा जाएगा और “व्याय विभाग”

(ii) इस प्रकार रखे गए शीर्षक के पश्चात् और उसके नीचे की प्रविष्टियों से पहले “बाल संस्कारण” उप शीर्षक का लोप किया जाएगा,

(iii) उप शीर्षक “बाल नामांकित पूर्ति विभाग” और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(क) “मानव संसाधन विकास संस्कारण” शीर्षक के अंतीम “(क) संस्कृति विभाग” उप शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अन्ति:-

“क. महिला और बाल विकास विभाग”

1. नियुक्ति कल्याण।

2. सभी और बाल कल्याण और इस विभाग के संबंध में श्रम संस्कृतियों और संगठनों के कार्यकालांकों का समन्वय।

3. लिंगों और जन्मों के दृष्टिभौतिक के बारे में संयुक्त राष्ट्र मंडल में प्राप्त विवरण।

4. विकासमय व्रेता से पूर्व शिक्षणों की वेदान्तान।

5. राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का समन्वय, प्रविष्टियां बालकों का आहार पोषण और महिलाओं को पोषणाहार निकाल।

6. इस विभाग को आवंटित विषयों से संबंधित पूर्ति और व्यायिक विष्याल।

7. इस विभाग की आवंटित विषयों के संदर्भ में स्वैच्छिक प्रवासीों का उन्नयन और विकास।

8. इस सूची में वित्तियिक विषयों में से किसी से संबंधित अन्य सभी संलग्न वा अवैधत वार्तालाल व्यायाम संग्रह।

9. सभी तथा सहको अनेकित व्यापार दस्त अधिनियम, 1956 (1956 का 104)।

10. दृष्टि निवेदन अधिनियम, 1961 (1961 का 28)।

11. कोलापरेटिव अमेरिकन रिलाइ एवरीबेयर के विधावस्ताओं का समन्वय।

12. महिलाओं और जन्मों के कल्याण से संबंधित योजना अनुसंधान भूज्यांकन मानिटर करना, परियोजना बनाना, आंकड़े और प्रयोगशैष।

13. संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल नियम (युनिसेफ)।

14. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (के. स. क. बो.)

15. राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान (एन. आई. पी. नी. सी. डी.)

(घ) “उत्तोग संस्कारण” शीर्षक के अधीन “बालपनी कार्य विभाग” उप शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के प्रवालय नियमित उप शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:-

“ब. लोक उत्पाद विभाग”

1. उत्तरार्द्ध उत्पाद अपूरो जिसमें शौकोगिक प्रबंध पूल भी सम्मिलित है।

(घ) विभि और व्याय मंडलाल शीर्षक के स्वाम पर “विभि, व्याय और कंपनी कार्य संस्कारण” शीर्षक रखा जाएगा और “व्याय विभाग” उप शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के प्रवालय नियमित उप शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:-

“ब. कंपनी कार्य विभाग”

1. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) का प्रशासन।

2. कंपनी (राष्ट्रीय नियमियों को बाल) अधिनियम, 1951 (1951 का 54) का प्रशासन।

3. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) का प्रशासन।

4. लेखा-बृति (बाटर्ड एकार्डनेट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) लागत और संकर्म लेखा बृद्धि (लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) कंपनी मधिष्ठान बृति (कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56))।

5. कंपनियों से संबंधित आनंदों का संग्रहण।

6. भारीवारी विभि के संबंध में विधान और भारीवारी भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अध्याय 7 के अधीन के व्यवहारिक विधानों के कर्तिपद्धति व्यवहार नियंत्रण (अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारों में विहित है)।

7. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आवेदन।

8. अपर्याप्ति मधों में किसी के बारे में केवल प्रशासित लेखों से संबंधित मधों की बाबत लेख का उत्तरवाचिक।

9. केन्द्र प्रशासित भेदों में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 1860 (1860 का 21) के यथीन सोसायटियों के रजिस्ट्रीकरण और हस्तों के प्रयोग से संबंधित विधान ।

(ट) “विधि, न्याय और कानूनी कार्य मंत्रालय” शीर्षक और उसके भीष्मी की इस प्रकार संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“वास मंत्रालय”

1. वास और खनिज (विविधम और विकास) प्रधिनियम, 1957 (1957 का 66) तथा अन्य संबंधितियों के अधीन आनें तथा कानून और सिम्लाईट तथा भरणार्थ आनु से विभिन्न अनियों के विकास का विनियम, जिसके अन्तर्गत विविध राज्यों से संबंधित प्रश्न और इनके बारे में अनुसंधान कार्य है ।
2. सभी ऐसी अन्य धारा और खनिज, जो विनिर्दिष्टतया किसी अन्य विभाग को आवंटित नहीं है जैसे अस्त्रमिनियम, जम्ता, ताका सोना, हीरे, सीता और निकल ।
3. इस विभाग द्वारा अवहृत सभी उद्दोगों की योजना विकास और नियंत्रण तथा सहायता ।
4. भारतीय भू-विभाग संबंध ।
5. भारतीय ज्ञान व्यूह ।
6. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित हस्ती संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।
7. वि सिविकम मार्हिनिंग कारपोरेशन लिमिटेड ।
8. जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टतया आवंटित किए गए हैं, उनके सिवाएँ इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अधीन विविक सेक्टर उद्यम और उपकरण ।
9. मैटलजिकल प्रेड सिलिकोन ।

(उ) (i) “पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय” शीर्षक के स्थान पर “रेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय” शीर्षक रखा जाएगा ।

(ii) “क” पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग “उप शीर्षक का लोप किया जाएगा” ।

(iii) “ब रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग” उप शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(द) “योजना मंत्रालय” और “कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय” शीर्षकों और उसके भीष्मी की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“योजना और कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय”

क. योजना विभाग

राष्ट्रीय योजना के विषय की बाबत संसद के प्रति उत्तरदायित्व ।

ख. सांख्यिकी विभाग

1. सांख्यिकी के क्षेत्र में आनंदों के संबंध, प्रसंस्करण की संकल्पना और परिभावाएँ, कार्य प्रणाली और परिणामों का प्रसार अन्तर्वर्षित करते हुए प्रमाणों और मानकों की प्राप्तिकालित करता और उनका अनुरक्षण ।
2. भारत सरकार के विभागों के संबंध में या तो आनंदों की उपलब्धता में किसी भ्रातारतम्भ की विभागानता को या तांखिकी भवन के द्विगुणीकरण को पहचानते की दृष्टि से सांख्यिकी कार्य या समन्वयन करता और प्रावस्थक उपचारी उपचारों का सुलगव देना ।
3. सांख्यिकी कार्य प्रणाली की बाबत और संप्रीति आनंदों सांख्यिकी विभाग पर भारत सरकार के विभागों को सलाह देना ।
4. भारतीय सांख्यिकी में का प्रबल्ल करने के केन्द्रीकृत वहलू और उस सेवा के लिए प्रशिक्षण, फैरियर विषयक योजना और नमूना योजना से संबंधित सभी विषय ।
5. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ।
6. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ।
7. संगणक (कंप्यूटर) केन्द्र ।
8. भारतीय सांख्यिकी संस्थान ।
9. कार्यक्रम कार्यालय विभाग
1. 20 सूची कार्यक्रम को मानीटर करना ।
2. असंरचना सैक्टरों के कार्य-सम्पादन को मानीटर करना, और
3. शीस करोड़ रुपए और उसके ऊपर की परियोजनाओं को मानीटर करना ।

(प) इस प्रकार रुपए योजना और कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय” शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंतर्स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“विद्युत और भ्रातारंपरिक ऊर्जा लोत मंत्रालय”

क. विद्युत विभाग

1. ऊर्जा के क्षेत्र में साधारण नीति ।
2. अनुसंधान विकास, तकनीकी सहायता और जल विद्युत और ऊर्जीय शक्ति से संबंधित यामले (3 बेंगांवाट कमता की ओर उससे कम की लक्ष्यसंतोष हाइड्रल परियोजनाएँ और भू-तापीय ऊर्जा) ।
3. भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का 9) ।
4. विद्युत (प्रवाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54)
5. केन्द्रीय विद्युत बोर्ड ।
6. केन्द्रीय विद्युत प्रशिक्षण ।
7. संघ राज्य योगों में विद्युत स्त्रीये ।
8. दामोदर धाटी निगम ।
9. भारत व्यास प्रबंध बोर्ड और व्यास सम्निवार्ण बोर्ड (सिल्वर से संबंधित विषयों को छोड़कर) ।
10. राष्ट्रीय साप विद्युत निगम लिमिटेड ।
11. राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड ।
12. ग्रामीण विद्युतीकारण निगम लिमिटेड ।
13. उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड ।
14. केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान ।
15. विद्युत शक्तीनियर प्रशिक्षण सोसाइटी ।

ख. भ्रातारंपरिक ऊर्जा लोत विभाग

1. बायो-नीस का अनुसंधान और विकास तथा बायो-नीस यूनिटों से संबंध कार्यक्रम ।
2. भ्रातिरिक्ष ऊर्जा लोत भ्रायोग (सी.ए.एस.ई.) ।
3. सीर ब्रकाश बोल्टीय यंत्र उनके विकास, ब्रकाश और अनुप्रयोगों सहित ।

4. 3 मेगावाट क्षमता की और उससे कम की लक्ष्य/संधर्म हाइड्रल परियोजनाएं और भूतार्पीय ऊर्जा।
5. समूम्हत चूल्हों और उनके अनुसंधान तथा विकास से संबंधित कार्यक्रम।
6. भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्रशिकरण।

(त) इस प्रकार अंतर्स्थापित “विद्युत और आपारांपरिक ऊर्जा क्रोत मंत्रालय” शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियों अंतर्स्थापित की जाएंगी, इव्वत्:—

शामीण विकास मंत्रालय

1. पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामले।
2. भूमि सुधार, भूमि विकास, भूमि रेकार्ड, जोतों की चकवन्नी तथा अन्य संबंधित मामले।
3. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का प्रशासन और संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन संबंधी अन्य मामले।
4. किसी राज्य में उस राज्य से बाहर वैदा द्वारा कर विवरक दावों तथा अन्य सांबंधित प्रशिकरणाओं को, जिनके अंतर्गत भू-राजस्व बकाया, और इस प्रकार वसूल की जाने वाली बकाया भी है, वसूली।
5. भूमि अर्जन भाटक का संग्रहण, भूमि का हस्तान्तरण और अन्य संक्रामण, भूमि सुधार और कृषि संबंधी उद्धार, जिनके अंतर्गत विवरणों और नगर योजना सुधारों के लिए कृषि भूमि से भिन्न भूमि का अर्जन नहीं है।
6. भू-राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्माण और संग्रहण, राजस्व प्रयोजनों के लिए परिमाप और राजस्व का अन्य संक्रामण भी है।
7. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क।
8. प्रारंभिक विकास, श्रीक विकास, शामीण स्वास्थ्य, शामीण विद्युती-करण और पीवहार कार्यक्रमों के लेख में शामीण लेखों की अनुत्तम प्रावश्यकता कार्यक्रम से संबंधित सभी मामलों का नोडीय उत्तराधिकार।
9. शामीण लेखों से संबंधित जल प्रदाय, भवनाली जल निकास और स्वच्छता। इस लेख में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता।
10. (क) शामीण रोजगार या बेरोजगारी से संबंधित सब विषय जैसे शामीण विकास की नीतियां और कार्यक्रम जिसके अंतर्गत ‘विशेष’ संकरण, मजदूरी या शाय में वृद्धि भी है, नैवार करना, उससे संबंधित प्रशिकरण।
- (ख) शामीण रोजगार के विनिविष्ट कार्यक्रम का कार्यान्वयन, जैसे राष्ट्रीय शामीण रोजगार कार्यक्रम (रा.शा.रो.का.) शामीण भूमिकाएं रोजगार, गारणी कार्यक्रम (ग्रा.भ.रो.का.) और समय समय पर बनाए गए कार्यक्रम।
- (ग) शामीण रोजगार या बेरोजगार से संबंधित माइको स्टार आयोजन तथा उसके लिए प्रशासनिक हाईका।
11. संबंधित शामीण विकास जिसमें लघु कृषि का विकास प्रशिकरण, सीमांत कृषक और कृषि मजदूर, सूखा प्रबल लेख कार्यक्रम आदि सम्मिलित हैं।
12. सक्षमता विकास कार्यक्रम।
13. लोक सहायार, जिसके अंतर्गत शामीण विकास के लिए स्वयंसेवी प्रशिकरणों और राष्ट्रीय शामीण विकास निविं से संबंधित सब विषय भी हैं।

14. शामीण लेखों में भविष्यारण व्यवस्था जिसमें शामीण नोटाम आते हैं।
15. शामीण आवास जिसके अंतर्गत शामीण आवास नोटाम भी है और देश में उससे संबद्ध और आनुशंशिक सभी मामले या शामीण योजना, जहां तक उसका संबंध शामीण लेखों से है।
16. शामीण लेखों में कृषि मंडियों की स्थापना और कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) प्रशिकरण, 1937 (1937 का 1)।
17. इस संघीयी भी मदों से संबंधित भविकारी समितियां।
18. इस मूली में विनिविष्ट लिखी भी विषय संबंधित सभी सबद तथा अधीनसत्य कार्यान्वय तथा अन्य संगठन।
19. शामीण लेखों में अनुत्तम प्रावश्यकता कार्यक्रम के मामलों सहित शामीण सङ्कारों से संबंधित सभी मामले।
20. असम के उत्तर जनजाति लेखों में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या अंतर्गत: वित्त पोषित सङ्कर संकर्म जो संविधान को छठी अनुसूची के पर्य 20 से उपाव सारणी के भाग I और II में विनिविष्ट हैं।
2. कोप्रापरेशन वित्त सेंटर फार इंटेरेस्ट रुल इवलपरमेंट फार एशिया एंड ऐसिफिक (मो.प्रार्ट.आर.डी.ए.पी.) तथा वि एको एशियन रुल इंस्ट्रुमेंट आनाइजेशन (ए.ए.प्रार.आर.डी.) से संबंधित सभी मामले।

(थ) (1) “इस्पात और आन मंत्रालय” शीर्षक के स्थान पर “इस्पात मंत्रालय” शीर्षक द्वारा जाएगा,

(2) “क. इस्पात विभाग” उप शीर्षक का भोप किया जाएगा,

(3) “ख. आन विभाग” उप शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ब) “कल्याण मंत्रालय” शीर्षक के अधीन “क. कल्याण विभाग” उप शीर्षक का लोप किया जाएगा और “ख. महिला और बाल विकास मंत्रालय” उप शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों का भी लोप किया जाएगा।

रामस्वामी वेंकटरामन
“राष्ट्रपति”

[सं. 74/2/11/9/-वंति.]

शीर्षक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 1991

S.O. 452(E).- In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Two hundred and Seventeenth & Amendment Rules, 1991.
- (2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961; (hereinafter referred to as the said rules) for the First Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"THE FIRST SCHEDULE"

(Rule 2)

**MINISTRIES, DEPARTMENTS, SECRETARIATS
AND OFFICES**
(MANTRALAYA, VIBHAG, SACHIVALAYA
TATHA KARYALAYA)

1. Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya):
(i) Department of Agriculture and Cooperation (Krishi aur Sahakari Vishag).
(ii) Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan aur Shiksha Vibhag).
(iii) Department of Animal Husbandry and Dairying (Pashupalan aur Dairy Vibhag).
2. Ministry of Chemicals & Fertilizers (Rasayan aur Urvarak Mantralaya).
(i) Department of Chemicals and Petro-Chemicals (Rasayan aur Petro-Rasayan Vibhag).
(ii) Department of Fertilisers (Urvarak Vibhag).
3. Ministry of Civil Aviation and Tourism (Nagar V�taran aur Paryatan Mantralaya).
(i) Department of Civil Aviation (Nagar V�taran Mantralaya).
(ii) Department of Tourism (Paryatan Vibhag).
4. Ministry of Civil Supplies & Public Distribution. (Nagrik Poorti aur Sarvajatiik Vitaran Mantralaya.)
5. Ministry of Coal (Koyalā Mantralaya).
6. Ministry of Commerce (Vaniija Mantralaya).
(i) Department of Commerce (Vaniija Vibhag).
(ii) Department of Supply (Poorti Vibhag).
7. Ministry of Communications (Sanchat Mantralaya).
(i) Department of Posts (Dak Vibhag).
(ii) Department of Telecommunication (Doordarshan Vibhag).
8. Ministry of Defence (Raksha Mantralaya).
(i) Department of Defence (Raksha Vibhag).
(ii) Department of Defence Production and supplies (Raksha Utpadan aur Poorti Vibhag).
(iii) Department of Defence Research and Development (Raksha Anusandhan aur Vikas Vibhag).
9. Ministry of Environment and Forests (Paryavaran aur Van Mantralaya).
10. Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya).
11. Ministry of Finance (Vitta Mantralaya).
(i) Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag).
(ii) Department of Expenditure (Vyaya Vibhag).
(iii) Department of Revenue (Rajaswa Vibhag).
12. Ministry of Food (Khadya Mantralaya).
13. Ministry of Food Processing Industries (Khadya Prasanskaran Udyog Mantralaya).
14. Ministry of Health and Family Welfare (Swasthya aur Pariwar Kalyan Mantralaya).

- (i) Department of Health (Swasthya Vibhag).
(ii) Department of Family Welfare (Parivar Kalyan Vibhag).
15. Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya).
(i) Department of Internal Security (Antarik Suraksha Vibhag).
(ii) Department of States (Rajya Vibhag).
(iii) Department of Official Language (Raj Bhasha Vibhag).
(iv) Department of Home (Grih Vibhag).
16. Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantralaya).
(i) Department of Education (Shiksha Vibhag).
(ii) Department of Youth Affairs and Sports (Yuva Karyakram aur Khel Vibhag).
(iii) Department of Arts (Kala Vibhag).
(iv) Department of Culture (Sanskriti Vibhag).
(v) Department of Women and Child Development (Mahila aur Bal Vikas Vibhag).
17. Ministry of Industry (Udyog Mantralaya).
(i) Department of Industrial Development (Audyogik Vikas Vibhag).
(ii) Department of Heavy Industry (Bhari Udyog Vibhag).
(iii) Department of Public Enterprises (Lok Udyam Vibhag).
(iv) Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries. (Laghu Udyog aur Krishi Evam Gramin Udyog Vibhag).
18. Ministry of Information and Broadcasting (Soochana aur Prasarhan Mantralaya).
19. Ministry of Labour (Shram Mantralaya).
20. Ministry of Law and Justice and Company Affairs (Vidhi, Nyaya aur Kampani Karya).
(i) Department of Legal Affairs (Vidhi Karya Vibhag).
(ii) Legislative Department (Vidhayee Vibhag).
(iii) Department of Justice (Nyaya Vibhag).
(iv) Department of Company Affairs (Kampani Karya Vibhag).
21. Ministry of Mines (Khan Mantralaya).
22. Ministry of Parliamentary Affairs (Sansadhiya Karya Mantralaya).
23. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Karmik Lok Shikayat tatha Pension Mantralaya).
(i) Department of Personnel and Training (Karmik aur Prashikshan Vibhag).
(ii) Department of Administrative Reforms and Public Grievances (Prashasanik Sudhar aur Lok Shikayat Vibhag).
(iii) Department of Pensions and Pensioners Welfare (Pension aur Pension Bhogi Kalyan Vibhag).
24. Ministry of Petroleum and Natural Gas (Petroleum aur Prakritik Gas Mantralaya).
25. Ministry of Planning and Programme Implementation (Yojana aur Karyakram Karyanvayan Mantralaya).
(i) Department of Planning (Yojana Vibhag).
(ii) Department of Statistics (Sankhyiki Vibhag).

(iii) Department of Programme Implementation (Karyavayan Vibhag).

26. Ministry of Power and Non-Conventional Energy Sources (Vidyut aur Aparamparik Oorja Srota Mantralaya).

- Department of Power (Vidyut Vibhag).
- Department of Non Conventional Energy Sources (Aparamparik Oorja Srota Vibhag).

27. Ministry of Railways (Rail Mantralaya).

28. Ministry of Rural Development (Gramin Vikas Mantralaya).

29. Ministry of Science and Technology (Vigyan aur Praudyogiki Mantralaya).

- Department of Science and Technology (Vigyan aur Praudyogiki Vibhag).
- Department of Scientific and Industrial Research (Vigyan aur Audyogik Anusandhan Vibhag).
- Department of Bio-Technology (Biotechnology Vibhag).

30. Ministry of Steel (Ispat Mantralaya).

31. Ministry of Surface Transport (Jal Bhootal Parivahan Mantralaya).

32. Ministry of Textiles (Vastra Mantralaya).

33. Ministry of Urban Development (Shahari Vikas Mantralaya).

34. Ministry of Water Resources (Jal Sansadhan Mantralaya).

35. Ministry of Welfare (Kalyan Mantralaya).

36. Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).

37. Department of Electronics (Electroniki Vibhag).

38. Department of Ocean Development (Mahasagar Vikas Vibhag).

39. Department of Space (Antariksh Vibhag).

40. Cabinet Secretariat (Mantrikandal Sachivalaya).

41. President's Secretariat (Rashtrapati Sachivalaya).

42. Prime Minister's Office (Pradhan Mantri Karyalaya).

43. Planning Commission (Yojana Ayog).

3. In the Second Schedule to the said rules :—

(a) under the heading "Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya)", the sub-headings "C. Department of Rural Development (Gramin Vikas Vibhag)" and the "D. Department of Fertilizers (Urvarak Vibhag)" and the entries thereunder, shall be omitted.

(b) after the heading "Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya)" and the entries thereunder, the following shall be inserted, namely :—

"Ministry of Chemicals and Fertilizers (Rasayan Aur Urvarak Mantralaya)"

A. Department of Chemicals and Petro-Chemicals (Rasayan Aur Petro-Rasayan Vibhag).

- Drugs and Pharmaceuticals.
- Insecticides (excluding the administration of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968).
- Molasses-distribution and pricing.

4. Alcohol-industrial and potable (excluding 'lecoholic drinks from non-molasses base) including the Indian Power Alcohol Act, 1948 (22 of 1948).

5. Dye-stuffs and dye-intermediates.

6. All organic and inorganic chemicals, not specifically allotted to any other Ministry or Department.

7. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.

8. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified under this Department.

9. Public Sector projects concerned with the subjects included under this Department except such projects as are specifically allotted to any other Ministry or Department.

10. Bhopal Gas Leak Disaster—Special Laws relating thereto.

11. Petro-chemicals.

12. Industries relating to production of non-cellulosic synthetic fibres (Nylon Polyester, Acrylic etc.)

13. Synthetic rubber.

14. Plastics including fabrications of plastic and moulded goods.

15. All Public Sector units relating to the above matters.

16. All attached and subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

B. Department of Fertilizers (Urvarak Vibhag)

- Planning for fertilizer production including import of fertilizer through a designated canalising agency.
- Arrangements for movement and distribution of fertilizers in terms of allocations made by the Department of Agriculture and Cooperation.
- Management of subsidy for indigenous and imported fertilizers including determination of retention price and costing of imported fertilizers.
- Administration of the Fertilizers (Movement Control) Order, 1960.
- Administrative responsibility for public enterprises under the control of the Department.
- Public sector projects concerned with subjects included under this Department except such projects as are specifically allotted to any other Ministry or Department.
- Administrative responsibility for fertilizer production unit in the cooperative sector, namely, Indian Farmers Cooperative Limited (IFFCO), Krishak Bharti Cooperative Limited (KRIBHCO).
- Administrative responsibility for the Indian Potash Limited (IPL).
- All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified under this Department.

(c) (i) for the "Ministry of Civil Aviation (Nagar Vimanan Mantralaya)" the heading "Ministry of Civil Aviation and Tourism (Nagar Vimanan Aur Paryatan Mantralaya)" shall be substituted.

(ii) after the heading, as so substituted, and before the entries thereunder, the following sub-heading shall be inserted, namely :—

A. "Department of Civil Aviation (Nagar Vimanan Vibhag)".

(iii) after the sub-heading "A. Department of Civil Aviation (Nagar Vimanan Vibhag)" as so inserted, and the entries thereunder, the following sub-heading and the entries shall be inserted, namely :—

"B. Department of Tourism (Paryatan Vibhag)

1. Development of Tourism

2. India Tourism Development Corporation and Public Sector Hotels thereunder. Inquiries and Statistics for the purpose of any of the matters specified in this list".

(d) after the heading "Ministry of Civil Aviation and Tourism (Nagar Vimana Aur Paryatan Mantralaya)" and entries thereunder, the following shall be inserted, namely :—

"Ministry of Civil Supplies and Public Distribution (Nagrik Poorti Aur Sarvajanik Vitran Mantralaya)

1. Internal Trade.

2. Inter State Trade: the Spirituous Preparations (Inter-state Trade and Commerce) Control Act, 1955 (39 of 1955).

3. Control of Futures trading the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952).

4. The Essential Commodities Act, 1955 (Supply, Prices and distribution of essential commodities not dealt with specifically by any other Ministry).

5. Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (7 of 1980) persons subjected to detention thereunder.

6. Consumer Cooperatives.

7. Public Distribution Systems.

8. Monitoring of prices and availability of essential commodities.

9. The Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986).

10. Regulation of packaged Commodities.

11. Training in Legal Meteorology.

12. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to Vanaspati, Oil seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.

13. Price control of and inter-state trade and commerce in and supply and distribution of Vanaspati, Oils Seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.

14. Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats.

15. Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1952 (12 of 1950).

16. Standards of Weights and Measures. The Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976).

17. The Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

18. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list, including the Forward Markets Commission, Bombay".

(e) after the heading "MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (NAGRIK POORTI AUR SARVAJANIK VITRAN MANTRALAYA)" and the entries thereunder, as so inserted, the following heading and the entries shall be inserted namely:—

"MINISTRY OF COAL (KOYALA MANTRALAYA)"

1. Exploration and development of coking and non-coking coal and lignite deposits in India.

2. All matters relating to production, supply, distribution and prices of coal.

3. Development and operation of coal washeries other than those for which the Department of Steel (Ispat Vibhag) is responsible.

4. Low Temperature carbonisation of coal and production of synthetic oil from coal.

5. Administration of Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974).

6. The Coal Mines Provident Fund Organisation.

7. The Coal Mines Welfare Organisation.

8. Administration of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1948 (46 of 1948).

9. Administration of Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947).

10. Rules under the Mines Act, 1952 (32 of 1952) for the levy and collection of duty of excise on coke and coal produced and despatched from mines and administration of rescue fund.

11. Administration of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957).

12. Public Sector Enterprises dealing with coal and lignite.

13. Administration of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957) and other Union Laws in so far as the said Act and Laws relate to coal and lignite and sand for stowing, business incidental to such administration including questions concerning various States.

(f) the heading "MINISTRY OF ENERGY (OORJA MANTRALAYA)" and the entries thereunder shall be omitted.

(g) under the "MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FOREST (PARYAVARAN TATHA VAN MANTRALAYA)", the sub-heading "DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FOREST AND WILD LIFE (PARYAVARAN, VAN AUR VANYA JEEV VIBHAG)" shall be omitted.

(h) (i) for the heading "MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (KHADYA AUR NAGRJK POORTI MANTRALAYA)", the heading "MINISTRY OF FOOD (KHADYA MANTRALAYA)" shall be substituted;

(ii) after the heading, as so substituted, and before the entries thereunder, the sub-heading "A. DEPARTMENT OF FOOD (KHADYA VIBHAG)" shall be omitted;

(iii) the sub-heading "B. DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES (NAGRIK POORTI VIBHAG)" and the entries thereunder, shall be omitted.

(i) under the heading "MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSADAHN VIKAS MANTRALAYA)", after the sub-heading "D. DEPARTMENT OF CULTURE (SANSKRITI VIBHAG)"

and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely:—

"E. DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (MAHILA AUR BAL VIKAS VIBHAG)

1. Family Welfare.
2. Women and child welfare and coordination of activities of other Ministries and Organisations in connection with this subject.
3. References from the United Nations Organisation relating to traffic in women and children.
4. Care of pre-school children.
5. Coordination of National Nutrition Programme, Nutrition feeding of pre-school children and Nutrition education of women.
6. Charitable and religious endowments pertaining to subjects allocated to this Department.
7. Promotion and development of voluntary effort on subjects allocated to this Department.
8. All other attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
9. Administration of the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 (104 of 1956).
10. Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).
11. Coordination of activities of Cooperative American Relief Everywhere (CARE).
12. Planning, Research, Evaluation, Monitoring, Project Formulations, Statistics and Training relating to the welfare of women and children.
13. United Nations Children's Fund (UNICEF).
14. Central Social Welfare Board (CSWB).
15. National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD).

(j) under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)" for sub heading "B. DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS (KAMPANI KARYA VIBHAG)" and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be substituted, namely:—

"B. DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES (LOK UDYAM VIBHAG)

1. Bureau of Public Enterprises including Industrial Management Pool."

(k) for the heading "MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (VIDHI AUR NYAYA MANTRALAYA)", the heading "MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (VIDHI, NYAYA AUR KAMPANI KARYA MANTRALAYA)" shall be substituted and after sub-heading "C. DEPARTMENT OF JUSTICE (NYAYA VIBHAG)" and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely:—

"D. DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS (KAMPANI KARYA VIBHAG)

1. Administration of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).
2. Administration of the Companies (Donations of Nations Funds) Act, 1951 (54 of 1951).
3. Administration of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969).

4. Profession of Accountancy [Chartered Accountant Act, 1949 (38 of 1949)]; Profession of Costs and Works Accountancy [Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959)]; Profession of Company Secretaries [Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980)].

5. Collection of Statistics relating to Companies.
6. Legislation relating to law of Partnership and the exercise of certain functions under Chapter VII of the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) in centrally administered areas. (The administration of the Act vests in the State Governments).
7. Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission.
8. The responsibility of the Centre relating to matters concerning centrally administered areas in respect of any of the above items.
9. Legislation in relation to societies registration and exercise of functions under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) in centrally administered areas".

(1) after the heading "MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (VIDHI, NYAYA AUR KAMPANI KARYA MANTRALAYA)" and the entries thereunder, as so amended the following shall be inserted, namely:—

MINISTRY OF MINES (KHAN MANTRALAYA)

2. Regulation of mines and development of minerals other than coal and lignite and sand for stowing under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), and other Union Laws, including questions concerning various States and incidental business in respect of these.
2. All other metals and minerals not specifically allotted to any other Department, such as, aluminium, zinc, copper, gold, diamonds, lead and nickel.
3. Planning development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.
4. Geological Survey of India.
5. Indian Bureau of Mines.
6. All other Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
7. The Sikkim Mining Corporation Limited.
8. Public Sector enterprises and undertakings falling under the subjects included in this list, except such as are specifically allotted to any other Department.

9. Metallurgical Grade Silicon.

(m) (i) for the heading "MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (PETROLEUM AUR RASAYAN MANTRALAYA)", the heading "MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (PETROLEUM AUR PRAKRITIK GAS MANTRALAYA)" shall be substituted:

- (ii) the sub-heading "A. DEPARTMENT OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (PETROLEUM AUR PRAKRITIK GAS VIBHAG)" shall be omitted;
- (iii) the sub-heading "B. DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS (RASAYAN AUR PETRO-RASAYAN VIBHAG)" and the entries thereunder, shall be omitted.

(n) for the headings “MINISTRY OF PLANNING (YOJANA MANTRAI AYA)” and “MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (KARYAKRAM KARYANVAYAN MANTRALAYA)”, and the entries under the said headings, the following shall be substituted, namely:—

“MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (YOJANA AUR KARYAKRAM KARYANVAYAN MANTRALAYA).

A. DEPARTMENT OF PLANNING (YOJANA VIBHAG
Responsibility to Parliament in regard to the subject of national planning.

B. DEPARTMENT OF STATISTICS (SANKHYIKI VIGHAG)

1. Laying down and maintenance of norms and standards, in the field of statistics, involving concepts and definitions, methodology of data collection, processing of data and dissemination of results.
2. Coordination of statistical work with a view to identifying the existence of either gaps in data availability or the duplication of statistical work in respect of the Departments of the Government of India and to suggest necessary remedial measures.
3. Advise the Departments of the Government of India regarding the statistical methodology and on statistical analysis of collected data.
4. Centralised aspects of managing the Indian Statistical Service and all matters pertaining to training, career planning and manpower planning for that service.
5. Central Statistical Organisation.
6. National Sample Survey Organisation.
7. Computer Centre.
8. Indian Statistical Institute.

C. DEPARTMENT OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (KARYAKRAM KARYANVAYAN VIGHAG)

- (i) Monitoring of 20 point programme;
- (ii) Monitoring of the performance of Infrastructure sectors; and
- (iii) Monitoring of projects of Rs. 20 crores and above”.

(o) after the heading “MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (YOJANA AUR KARYAKRAM KARYANVAYAN MANTRALAYA)” and the entries thereunder, as so substituted, the following shall be inserted, namely:—

“MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (VIDYUT AUR APARAMPARIK, OORJA SROTA MANTRALAYA).

A. DEPARTMENT OF POWER (VIDYUT VIGHAG)

1. General Policy in the field of energy.
2. Research, development technical assistance and all matters relating to Hydro-electric and thermal power (except mini/micro hydel projects of and below 3 MW capacity and Geothermal energy).
3. Administration of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910).
4. Administration of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948).
5. Central Electricity Board.

6. Central Electricity Authority.
7. Power Schemes in Union Territories.
8. The Damodar Valley Corporation.
9. Bhakra Beas Management Board and Beas Construction Board (except matters relating to irrigation).
10. National Thermal Power Corporation Limited.
11. National Hydro-electric Power Corporation Limited.
12. Rural Electrification Corporation Limited.
13. North Eastern Electric Power Corporation Limited.
14. Central Power Research Institute.
15. Power Engineers Training Society.

B. DEPARTMENT OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (APARAMPARIK OORJA SROTA VIBHAG)

1. Research and development of bio-gas and programmes relating to bio-gas units.
2. Commission for Additional Sources of Energy (CASE).
3. Solar Photovoltaic devices, including their development, production and applications.
4. Mini/Micro hydel projects of and below 3 MW capacity and Geothermal energy.
5. Programmes relating to improved chulhas and research and development thereof.
6. Indian Renewable Energy Development Agency.”

(P) after the heading “MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (VIDYUT AUR APARAMPARIK OORJA SROTA MANTRALAYA)” and the entries thereunder, as so inserted, the following shall be inserted, namely:—

“MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS MANTRALAYA)

1. All matters relating to panchayati raj and panchayati raj institutions.
2. Land reforms, land tenures, land records, consolidation of holdings and other related matters.
3. Administration of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) and matters relating to acquisition of land for purposes of Union.
4. Recovery of claims in a State in respect of taxes and other public demands, including arrears of land revenue and sums recoverable as such arrears, arising outside that State.
5. Land, that is to say, collection of rents, transfer and alienation of land, land improvement and agricultural loans excluding acquisition of non-agricultural land or buildings, town planning improvements.
6. Land revenue, including the assessment and collection of revenue, survey of revenue purposes, alienation of revenues.
7. Duties in respect of succession to agricultural land.
8. Nodal responsibility for all matters relating to the Minimum Needs Programme in rural areas in the field of elementary education, adult education, rural health, rural electrification and the nutrition programmes.

9. Water supply, sewage, drainage and sanitation relating to rural areas. International cooperation and technical assistance in this field.
10. (a) All matters pertaining to rural employment or unemployment such as working out of strategies and programmes for rural employment including special works, wage or income generation and training related thereto;
- (b) Implementation of the specific programmes of rural employment such as National Rural Employment Programmes (NREP), Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLREP) and other programmes evolved from time to time.
- (c) Micro level planning related to rural employment or unemployment and administrative infrastructure therefor.
11. Integrated rural development, including small farmers development agency, marginal farmers and agricultural labourers, drought prone area programmes, etc
12. Desert Development Programmes.
13. Public cooperation, including all matters relating to voluntary agencies for rural development and National Fund for Rural Development.
14. Warehousing in rural areas, including rural godowns.
15. Rural housing including Rural Housing Policy and all matters germane and incidental thereto under country or rural planning, in so far as it relates to rural areas.
16. Setting up of agricultural markets in rural areas and the Agricultural produce (Grading and marking) Act, 1937 (1 of 1937).
17. Cooperatives relating to the items in this list.
18. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
19. All matters relating to rural roads including those under the Minimum Needs Programme in the rural areas.
20. Road works financed in whole or in part by the Central Government in tribal areas of Assam specified in Part I and Part II of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.
21. All matters relating to cooperation with the Centre for Integrated Rural Development for Asia and Pacific (CIRDAP) and the Afro-Asian Rural Reconstruction Organisation (AARRO);
- (q) (i) for the heading "MINISTRY OF STEEL AND MINES (ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA)", the heading "MINISTRY OF STEEL (ISPAT MANTRALAYA)" shall be substituted;
- (ii) the sub-heading "A. DEPARTMENT OF STEEL (ISPAT VIBHAG)" shall be omitted;
- (iii) the sub-heading "B. DEPARTMENT OF MINES (KHAN VIGHAG)" and the entries thereunder, shall be omitted.
- (r) under the heading "MINISTRY OF WELFARE (KALYAN MANTRALAYA)", the sub-heading "A. DEPARTMENT OF WELFARE (KALYAN VIBHAG)", shall be omitted and the sub-heading "B. DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (MAHILA AUR BAL VIKAS MANTRALAYA)" and the entries thereunder shall also be omitted.

R. VENKATARAMAN
PRESIDENT"

[F. No. 74/2/11 -Cab.]
D. DAS GUPTA, Joint Secy,